



THE STUDY
By Manikant Singh



ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ द लीजन ऑफ़ ऑनर

चर्चा में क्यों ?

- ◆ हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ द लीजन ऑफ़ ऑनर से सम्मानित किया गया।
- ◆ नेशनल ऑर्डर ऑफ़ द लीजन ऑफ़ ऑनर, या द लीजन ऑफ़ ऑनर, नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है और विश्व के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय सम्मानों में से एक है।
- ◆ पीएम मोदी फ्रांस की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं और वह पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस (बैस्टिल डे) परेड में सम्मानित अतिथि होंगे।

ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ द लीजन ऑफ़ ऑनर पुरस्कार के बारे में

- ◆ यह सम्मान आम तौर पर "राष्ट्र की सेवा" में फ्रांसीसी लोगों के योगदान को मान्यता देता है और यह पुरस्कार कभी-कभी फ्रांस की राजकीय यात्रा पर आये उच्च गणमान्य व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
- ◆ यह पुरस्कार 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा स्थापित किया गया था और पिछली दो शताब्दियों से अधिक समय से फ्रांसीसी राज्य प्रमुख की ओर से सभी क्षेत्रों में अपने सबसे योग्य नागरिकों को प्रस्तुत किया गया है। इस ऑर्डर का आदर्श वाक्य 'ऑनर एट पैट्री, फ्रेंच फॉर ऑनर और फादरलैंड' है।

पुरस्कार में शामिल है -

- ◆ पुरस्कार से कोई भौतिक या वित्तीय लाभ जुड़ा नहीं है। लीजन ऑफ़ ऑनर के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता; सरकार संभावित सम्मानित व्यक्तियों की पहचान करती है।
- ◆ पुरस्कार बैज ओक और लॉरेल पुष्पांजलि पर लटका हुआ पांच-सशस्त्र माल्टीज़ तारांकन है। सामने की तरफ गणतंत्र का पुतला है और पीछे दो तिरंगे झंडे हैं जो आदर्श वाक्य 'होन्नोर एट पैट्री' से घिरे हुए हैं। रिबन का रंग लाल है।



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669

- ◆ इस पुरस्कार को फ्रांस के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है। यह "प्राप्तकर्ताओं और उनके परिवारों के लिए गर्व का एक अमूल्य स्रोत है और नागरिक सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है"।

किसी विदेशी को लीजन से कब सम्मानित किया जा सकता है?

- ◆ किसी विदेशी व्यक्ति को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा सकता है, "यदि उन्होंने फ्रांस को सेवाएं (जैसे सांस्कृतिक या आर्थिक) प्रदान की हैं या मानवाधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता या मानवीय कार्रवाई के मुद्दों पर फ्रांस का समर्थन किया है"।

प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा पुरस्कार मिला है?

- ◆ लीजन ऑफ ऑनर में बढ़ती विशिष्टता की पांच श्रेणियां हैं: तीन रैंक - शेवेलियर (नाइट), ऑफिसर (अधिकारी), तथा कमांडर और दो उपाधियाँ - ग्रैंड ऑफिसर और ग्रैंड-क्रॉइक्स (ग्रैंड क्रॉस)। प्रधानमंत्री को भारत में भारत रत्न के समान सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया है।
- ◆ लीजन ऑफ ऑनर को किसी भी अन्य फ्रांसीसी या विदेशी प्रतीक चिन्ह से पहले बाई ओर पहना जाता है। अनौपचारिक पोशाक के साथ, लैपेल प्रतीक चिन्ह (रिबन या रोसेट) पहना जाता है।

भारत और ब्रिटेन की FTA वार्ता

चर्चा में क्यों ?

- ◆ वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा भारत और ब्रिटेन के बीच मौजूदा मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता में डिजिटल व्यापार, पर्यावरण और श्रम जैसे विवादास्पद मुद्दों से निपटने वाले पांच अध्यायों पर बातचीत बंद करने की घोषणा की है।
- ◆ इसके अलावा, दोनों देश FTA वार्ता के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और उत्पत्ति के नियमों तथा सेवा क्षेत्र में कुछ मतभेदों जैसे मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने के लिए भी काम कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- ◆ दोनों देशों के बीच FTA वार्ता के 26 अध्यायों में से 14 अध्यायों पर चर्चा बंद हो चुकी है और अन्य अध्यायों चर्चा की जा रही है।
- ◆ भारत-ब्रिटेन का FTA "सबसे जटिल" है जिस पर भारत द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे क्योंकि इसमें कई गैर-व्यापार मुद्दे भी हैं।



- ◆ यह FTA सबसे व्यापक FTA भी होगा जिस पर भारत ने किसी अन्य विकसित के साथ हस्ताक्षर नहीं किया है।
- ◆ भारत-कनाडा व्यापार समझौते के लिए नौवें दौर की वार्ता पर भी चर्चा की गयी।
- ◆ भारत-यूरोपीय संघ समझौते पर 5वें दौर की वार्ता के दौरान बाजार पहुंच प्रस्तावों के आदान-प्रदान के तौर-तरीकों पर चर्चा की आशंका की जा रही है।
- ◆ वस्तुओं और सरकारी खरीद पर चर्चा की गई और उसे अंतिम रूप दिया गया। छोटे और मध्यम उद्यम के विषय पर बातचीत संपन्न हो गई है और सरकारी खरीद पर भी सैद्धांतिक सहमति हुई।

NSO डेटा की समीक्षा

चर्चा में क्यों ?

- ◆ उपभोग व्यय और रोजगार पर घरेलू सर्वेक्षणों के अंतिम दौर के निष्कर्षों को खारिज किए जाने के बाद सरकार द्वारा 2019 में स्थापित आर्थिक सांख्यिकी (SCES) के स्थान पर, आधिकारिक डेटा के लिए एक नया आंतरिक निरीक्षण तंत्र गठित किया गया है।
- ◆ सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा आर्थिक सांख्यिकी (SCES), जो केवल आर्थिक संकेतकों की जांच करने का काम करता था, को सांख्यिकी पर एक स्थायी समिति (SCOS) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- ◆ भारत के पहले मुख्य सांख्यिकीविद् और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) के पूर्व अध्यक्ष प्रोनाब सेन को नई समिति की अध्यक्षता करेंगे। सांख्यिकी पर एक स्थायी समिति राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के तत्वावधान में किए गए सभी सर्वेक्षणों की रूपरेखा और परिणामों की समीक्षा करेगी।
- ◆ सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार, SCES , जिसे केवल आर्थिक संकेतकों की जांच करने का काम सौंपा गया था, को सांख्यिकी पर एक स्थायी समिति (SCOS) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसे सभी के ढांचे और परिणामों की समीक्षा करने का व्यापक जनादेश दिया गया है।



'सिस्टम ओवरहाल की जरूरत'

- ◆ SCOS में 10 आधिकारिक सदस्य और चार गैर-आधिकारिक सदस्य शामिल होंगे जो प्रतिष्ठित शिक्षाविद हों। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पैनल में अधिकतम 16 सदस्य हो सकते हैं।

'कोई डेटा नहीं है' उत्तर का महत्व

- ◆ प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय सहित सदस्यों द्वारा कहा गया कि भारत की सांख्यिकीय मशीनरी की तीखी आलोचना के बीच यह विकास महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की वकालत की थी और तर्क दिया था कि भारतीय सांख्यिकी सेवा के पास "सर्वेक्षण डिज़ाइन में बहुत कम विशेषज्ञता" है।
- ◆ "SCES का कार्यकाल किसी भी मामले में समाप्त हो रहा था, इसलिए आर्थिक डेटा से परे समिति के जनादेश का विस्तार करने और सभी सर्वेक्षणों के लिए तकनीकी पहलुओं पर मंत्रालय को सलाह देने का निर्णय लिया गया, जैसे- नमूना फ्रेम, डिज़ाइन, सर्वेक्षण पद्धति और अंतिम रूप देना।



डेटा अंतराल को प्लग करना

- ◆ सभी सर्वेक्षणों के विषय, परिणाम और कार्यप्रणाली पर समय-समय पर उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के अलावा, SCOS के संदर्भ की शर्तों में उन डेटा अंतरालों की पहचान शामिल है जिन्हें आधिकारिक आंकड़ों द्वारा भरने की आवश्यकता है, साथ ही उन अंतरालों को पाटने के लिए एक उचित रणनीति भी शामिल है। डेटा परिणामों में सुधार के लिए प्रशासनिक आंकड़ों के उपयोग का पता लगाना भी अनिवार्य किया गया है।
- ◆ पैनल, सर्वेक्षण परिणामों को अंतिम रूप देने में मदद करेगा, तो NSC के पास उन परिणामों के प्रकाशन को मंजूरी देने का अंतिम अधिकार होगा।
- ◆ सरकार ने NSC का पुनर्गठन किया था और चेन्नई गणितीय संस्थान में प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर को इसका अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया था।



- ◆ SCES, जिसमें 10 गैर-आधिकारिक सदस्यों सहित 28 सदस्य थे, की अध्यक्षता भी श्री सेन के द्वारा की गयी थी। पैनल को औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और श्रम बल के आंकड़ों से संबंधित आर्थिक संकेतकों के ढांचे की समीक्षा करने का आदेश दिया गया था। यह दायरा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और आर्थिक जनगणना जैसे डेटासेट तक सीमित था।



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669